



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 1993/चैत्र 17, 1915

No. 70]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 1993/CHAITRA 17, 1915

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1993

फा.सं. 17(4)/93-बीमा V:--सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के क्षेत्र में अनेक पहल की हैं जिनमें बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार शामिल हैं जिनका उद्देश्य एक ऐसी अधिक सक्षम और ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय प्रणाली का सृजन करना है जो इस समय किए जा रहे संरचनात्मक परिवर्तनों का ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त हो। बीमा समग्र वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग और इस क्षेत्र में इसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए इन मामलों पर गहराई से विचार करने और सिफारिश करने के लिए बीमा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- |   |         |
|---|---------|
| 1. श्री आर. एन. मल्होत्रा                                     | अध्यक्ष |
| 2. श्री आर. नारायणन<br>(पूर्व अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम)        | सदस्य   |
| 3. श्री आर. के. कुरुवाला<br>(पूर्व अध्यक्ष, साधारण बीमा निगम) | सदस्य   |

- |   |            |
|---|------------|
| 4. श्री प्रमत्त चन्द्र, आई. आई. एम. बंगलौर                    | सदस्य      |
| 5. डा. एस. ए. बवे, अध्यक्ष, यू टो आर                          | सदस्य      |
| 6. श्री आर. रामाकृष्णन, प्रेसिडेंट,<br>भारतीय बीमांकन सोसायटी | सदस्य      |
| 7. श्री दापक पारेख  | सदस्य      |
| 8. श्री एम. पी. मोदी, विशेष सचिव (बीमा)                       | सदस्य सचिव |

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

(1) वर्तमान ढांचे में बीमा उद्योग की जो संरचना तैयार हुई है उसकी जाँच करना तथा एक दक्ष और सक्षम बीमा उद्योग के उद्देश्य से इसकी मजबूती और कमजोरियों का मूल्यांकन करना ताकि बीमा सेवाओं और बीमा विधिताओं का दूर दूर तक विस्तार हो सके तथा लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला सेवाएं प्रदान की जा सकें और विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उद्योग की एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

(2) बीमा उद्योग की संरचना तथा नीति के सामान्य ढांचे में परिवर्तन संबंधी सिफारिश करना जो कि वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के अन्य पक्षों में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों का ध्यान में रखते हुए उपरोक्त लक्ष्यों के अनुसरण के लिए उपयुक्त हों।

(3) जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के संबंध में विशिष्ट सुझाव देना जिन्हें परिवर्तनशील आर्थिक वातावरण में इन संगठनों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु सह्यता मिलेगी।

(4) बीमा क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी मौजूदा ढांचे की समीक्षा करना और बदलते हुई अपेक्षाओं के अनुरूप विनियमकारी प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सिफारिशें करना।

(5) सर्वेक्षकों, मध्यस्थों तथा बीमा क्षेत्र के अन्य आनुवंशिक भागों की भूमिका और कार्य प्रणाली की समीक्षा करना और सिफारिशें करना।

ऐसे अन्य मामलों पर सिफारिशें करना जिन्हें समिति बीमा क्षेत्र के स्वास्थ्य और दीर्घाविधि विकास के लिए संगत समझे अथवा जो समिति द्वारा कोई गई अन्य सिफारिशों के परिणामस्वरूप हैं जिनमें जहां आवश्यक हो विधायन में परिवर्तन करना शामिल है।

समिति की अपनी रिपोर्ट 6 महीने के भीतर प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

स. एस. राव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

### RESOLUTION

New Delhi, the 7th April, 1993

F. No. 17(4)/93-Ins. V.—Government has taken a number of initiatives in the area of financial sector reforms covering the banking system and the capital markets aimed at creating a more efficient and competitive financial system suitable for the requirements of the economy keeping in mind structural changes currently underway. Insurance is an important part of the overall financial system and it is necessary to address the need for similar reforms in this sector. It has therefore been decided to appoint a Committee on Reforms in the Insurance sector to go into these issues in depth and make recommendations.

The Committee will consist of the following:—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Shri R. N. Malhotra   | Chairman |
| 2. Shri R. Narayanan<br>(former Chairman, LIC)                   | Member   |
| 3. Shri R. K. Daruwala<br>(former Chairman, GIC)                 | Member   |
| 4. Shri Prasanna Chandra,<br>IIM Bangalore                       | Member   |
| 5. Dr. S. A. Dave, Chairman, UTI                                 | Member   |
| 6. Shri R. Ramakrishnan, President<br>Actuarial Society of India | Member   |
| 7. Shri Deepak Parekh  | Member   |

8. Shri M. P. Modi, Special Secretary (Insurance) Member Secretary

The terms of reference of the Committee will be as follows :—

- (i) To examine the structure of the Insurance industry as it has evolved within the existing framework and to assess its strengths and weakness in terms of the objective of creating an efficient and viable insurance industry providing a wide reach of insurance services and a variety of insurance products with a high quality of service to the public and serving as an effective instrument for mobilisation of financial resources for development.
- (ii) To make recommendations for changes in the structure of the insurance industry, as well as the general framework of policy, as may be appropriate for the pursuit of the above objectives keeping in mind the structural changes currently underway in other parts of the financial system and in the economy.
- (iii) To make specific suggestions regarding LIC and GIC, which would help to improve the functioning of these organisations in the changing economic environment.
- (iv) To review the present structure of regulation and supervision of the insurance sector and to make recommendations for strengthening and modernising the regulatory system in tune with changing requirements.
- (v) To review and make recommendations on the role and functioning of surveyors, intermediaries and other ancillaries of the insurance sector.
- (vi) To make recommendations on such other matters as the Committee consider relevant for the health and long term development of the insurance sector or which are consequential on other recommendations made by the Committee, including changes in legislation where necessary.

The Committee should submit its report within six months.

C. S. RAO, Jt. Secy.